


 पत्रांक- 2481/कौशल विकास  
 दिनांक- 28/02/19.

मुख्य सचिव,

झारखण्ड स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की कार्यप्रणाली के संबंध में अधोहस्ताक्षरी की चर्चा टिप्पणी संख्या-मंत्री कोषांग-2446/दिनांक-07.02.2019 के संदर्भ में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के मिशन निदेशक ने पत्रांक-झा0कौ0वि0मि0-स्था-30/2019-421, दिनांक 15.02.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को एक प्रतिवेदन भेजा है। सरसरी तौर पर इसके अवलोकन से धारणा बन रही है कि सोसाईटी के लिये नियुक्त तकनीकी परामर्शी (earnst & young) की चयन प्रक्रिया में RFP की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तथा चयनोपरांत इन शर्तों के अनुपालन में अनियमितताएं हुई हैं और हो रही हैं, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निविदा हासिल करने के लिये चयनित परामर्शी ने जो निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसमें उल्लिखित विशेषज्ञों की योग्यता एवं अनुभव के बारे में तथ्य छुपाये गये या सही रूप में प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके कारण चयन की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई। चयन के उपरांत भी चयनित परामर्शी RFP की शर्तों का लगातार उल्लंघन करते रहा है। कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा जानबूझकर अथवा अनजाने में इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चयनित परामर्शी को चयन प्रक्रिया के दौरान एवं चयन प्रक्रिया के उपरांत झारखण्ड कौशल विकास मिशन और झारखण्ड सरकार के उच्चातर एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग द्वारा अनावश्यक संरक्षण दिया जा रहा है। इसे सांठ-गांठ की संज्ञा दिया जाना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसका क्या प्रभाव झारखण्ड सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास कार्य की गुणवत्ता पर पड़ रहा है यह अलग से विचार का विषय है। मेरी जानकारी के अनुसार जितनी संस्थाएँ राज्य में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिये चयनित की गई हैं और जिस प्रकार इनके द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण की निगरानी चयनित परामर्शी द्वारा की जा रही है वह भी संदेह के घेरे में है। इस बारे में निम्नांकित बिंदु ध्यान देने योग्य हैं:-

1. RFP के पृष्ठ संख्या-11 पर Key Experts की परिभाषा दी गई जो स्वतः स्पष्ट है। इसके अनुसार Key Experts पूर्णकालिक होने चाहिये। यानी जब तक राज्य सरकार के साथ एकरारनामा के अनुसार चयनित परामर्शी कार्य करेगा तबतक ये Key Experts उसके साथ वेतनमान के आधार पर

काम करेंगे। अधोहस्ताक्षरी को मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों के अनुलग्नक-2 पर 15 ऐसे विशेषज्ञों के नाम अंकित हैं। इसके अनुलग्नक-4 पर परामर्शी के चयनोपरांत कार्यरत एवं योगदान नहीं देने वाले ऐसे विशेषज्ञों का विवरण है। इनके तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि तकनीकी परामर्शी ने जिन 15 Key Experts का नाम, योग्यता एवं अनुभव का विवरण निविदा प्रस्ताव में दिया था उनमें से केवल 7 विशेषज्ञ ही चयनोपरांत परामर्शी के कार्य में योगदान किये। शेष 8 ने योगदान नहीं किया। सवाल उठता है कि कौशल विकास मिशन ने इस बारे में परामर्शी से जानकारी लिया या नहीं कि किस कारण से इन 8 Key Experts ने योगदान नहीं दिया? RFP में Key Experts के बारे में कहा गया है कि ये परामर्शी के साथ पूर्णकार्य अवधि तक काम करेंगे और वेतनमान पर काम करेंगे। क्या कौशल विकास मिशन ने यह जानने का प्रयास किया कि जिन Key Experts ने चयनोपरांत परामर्शी के साथ योगदान दिया है वे इनके साथ वेतनमान पर पूर्णकार्य अवधि तक के लिये काम कर रहे हैं या एक निश्चित समय के लिये टेका पर काम कर रहे हैं। साथ ही जिन 8 Key Experts ने परामर्शी के साथ इस काम में योगदान करने से इनकार कर दिया उसका कारण भी यही था कि तकनीकी परामर्शी इन्हें पूर्णकाल तक एक सुनिश्चित वेतनमान पर नियुक्त नहीं करना चाह रहे थे और टेकाकर्मी की तरह अंशकालीन शर्तों पर उनसे काम कराना चाहते थे। इन प्रश्नों के उत्तर से यह स्पष्ट हो पायेगा कि चयनित तकनीकी परामर्शी ने निविदा हासिल करने के लिये इन सभी 15 Key Experts का नाम, योग्यता एवं अनुभव का उल्लेख अपने निविदा प्रस्ताव में कर दिया था ताकि इनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर निविदा मूल्यांकन के समय प्राप्त अंकों के आधार पर वह निविदा हासिल कर ले और बाद में उनके स्थान पर कम योग्यता वाले विशेषज्ञों से काम करायें। अगर ऐसा है तो चयनित तकनीकी परामर्शी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिये। उसे अविलंब कार्यमुक्त करना चाहिये और उसे काली सूची में डालना चाहिये। तकनीकी परामर्शी के चयन के उपरांत कौशल विकास मिशन के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिये और उनके विरुद्ध भी लापरवाही/सांठगांठ के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिये।

2. RFP के पृष्ठ संख्या-15 के बिंदु 14.3 के अनुसार यदि तकनीकी परामर्शी के निविदा प्रस्ताव में उल्लिखित Key Experts प्रस्ताव जमा करने के वक्त परामर्शी के साथ कार्यरत नहीं है या उनका नाम बाद में जोड़ दिया गया है तो ऐसा प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। कौशल विकास मिशन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये गये कागजातों के अनुलग्नक-4 पर अंकित विवरण से स्पष्ट है कि तकनीकी परामर्शी द्वारा प्रस्ताव जमा करने के वक्त ये Key Experts परामर्शी के साथ कार्यरत

(3)

नहीं थे बल्कि वे अन्यत्र कार्यरत थे। यह RFP की शर्तों का उल्लंघन है और सरकार तथा तकनीकी परामर्शी के बीच हस्ताक्षरित एकरारनामा का पूरा उल्लंघन है। सवाल उठता है कि इस बारे में झारखंड कौशल विकास मिशन के अधिकारियों ने तथ्य जानने का प्रयास किया था या नहीं?

3. RFP के पृष्ठ संख्या-15 के बिंदु 14.4 का भी इस क्रम में खुला उल्लंघन हुआ है। अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त कागजातों के अनुलग्नक-2 एवं अनुलग्नक-4 पर अंकित विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से पता चलता है कि तकनीकी परामर्शी ने आधा से अधिक Key Experts को चयन के समय ही बदल दिया था। तकनीकी परामर्शी को यह सुनिश्चित करना था कि उसके चयन के दो वर्ष तक 60 प्रतिशत ऐसे विशेषज्ञ बदले नहीं जायेंगे, परंतु अभी तक करीब 75 प्रतिशत Key Experts बदल दिये गये। सवाल उठता है कि ऐसे बदलाव की अनुमति तकनीकी परामर्शी ने किसी सक्षम प्राधिकार से लिया या नहीं? यदि जिस सदस्य पदाधिकारी से अनुमति ली गई उसने निविदा प्रपत्र एवं एकरारनामा की प्रासंगिक शर्तों का ध्यान रखा या नहीं?
4. RFP के पृष्ठ संख्या-16 के बिंदु 17.1 में अंकित है कि Key Experts के Sub Contracting की अनुमति नहीं है और सभी Key Experts तकनीकी परामर्शी के साथ वेतनमान पर रहेंगे। तकनीकी परामर्शी ने इस शर्त का भी उल्लंघन किया है। झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन की ओर से दिये गये कागजातों के अनुसार चयनित परामर्शी एक अवधि विशेष तक के लिये नियुक्त ठेका आधारित Key Experts से काम करवाते रहा है और अपनी सुविधानुसार इन्हें बदलते रहा है।
5. इसी प्रकार RFP के पृष्ठ संख्या-18 के बिंदु 22.3 और 23.1, पृष्ठ संख्या-24 के बिंदु 46.2 और पृष्ठ संख्या-38 पर अंकित तकनीकी मूल्यांकन की शर्तों का भी घोर उल्लंघन हुआ है। निविदा की इस शर्त का भी चयनित परामर्शी ने अविवेकपूर्ण उल्लंघन किया है जिसके अनुसार यदि अपरिहार्य कारणवश किसी Key Experts को बदलने की नौबत आती है तो उसके स्थान पर नियुक्त किये जाने वाला Key Experts उससे बेहतर योग्यता और अनुभव का होना चाहिये। अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-4 में अंकित हटाये गये और इनकी जगह लिये गये Key Experts की सूची को सरसरी तौर पर देखने से पता चल जाता है कि नियुक्त किये गये विशेषज्ञों की योग्यता और अनुभव हटाये गये विशेषज्ञों की योग्यता और अनुभव से काफी कम है। यह चयनित एवं कार्यरत परामर्शी द्वारा की गई घोर धांधली है और वित्तीय अनियमितता है।

इस चयनित परामर्शी को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करानी है। झारखंड सरकार द्वारा मुख्य रूप से 4 प्रकार के संस्थायें कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नियुक्त की गई हैं:-

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 25 प्रतिशत।
2. सक्षम झारखंड कौशल विकास केन्द्र।
3. दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र (मेगा सेंटर)।
4. कॉलेज स्विच डेवलपमेंट प्रोग्राम।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर राज्य सरकार का सालाना करीब 50 से 60 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के मुताबिक इनका संचालन हो रहा है या नहीं यह देखने का काम उर्पयुक्त चयनित परामर्शी के जिम्मे है जिसके साथ सरकार ने करीब 5 वर्षों के लिये 50 करोड़ रुपये का करार किया है। करार के अनुसार इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भुगतान चयनित परामर्शी को सरकार नहीं करेगी। परंतु राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्न प्रकार के अन्यान्य वित्तीय भुगतान भी इसके अतिरिक्त परामर्शी को किया जा रहे हैं। यह वित्तीय अनियमितता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास केन्द्रों में गुणवत्ता एवं वित्तीय भुगतान की उन शर्तों का पालन भी नहीं हो रहा है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को विभिन्न स्तर पर किये जानेवाले भुगतान संदेहास्पद है। अंतिम 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को रोजगार देने की एवज में किया जाना है। इसमें भारी फर्जीवाड़ा हुआ है और हो रहा है। 12 जनवरी 2018 को राज्य सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर कौशल विकास केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त 26000 युवकों को रोजगार देने की घोषणा किया। इन सभी 26000 युवकों के नाम, पता, मोबाईल नंबर, नियोक्ता तथा वेतनमान आदि का ब्यौरा चौंकाने वाला है। संयोगवश इसकी साफ्ट कॉपी सूची मुझे प्राप्त हुई है। उस सूची में अंकित विवरण और युवकों के नाम, पता, फोन नंबर तथा नियोक्ता से संपर्क करने से स्पष्ट हो रहा है कि 3000 से अधिक युवकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं और जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उनमें से भी कितने ने योगदान दिया और योगदान देने के बाद कितने अभीतक कार्यरत हैं यह कहना मुश्किल है। झारखंड में कौशल विकास कार्यक्रम के इस फर्जीवाड़ा की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये। इसी प्रकार 12 जनवरी 2019 को भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर झारखंड सरकार ने कौशल विकास मिशन के अधीन चल रहे कौशल विकास केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त एक लाख से अधिक युवकों को रोजगार दिलाने की महत्वाकांक्षी घोषणा की है। मुझे जो सूचनायें प्राप्त हो रही हैं उनके आधार पर यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इसका नतीजा भी गत वर्ष की गई घोषणा से अलग नहीं होगा। कुल मिलाकर यह राजकीय कोष का भारी दुरुपयोग का मागला है। इसकी जांच होनी चाहिये।

(5)

समें चयनित परामर्शी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिये और कौशल विकास केन्द्र के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिये।

अंत में मैं कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) की नियुक्ति में बरती गई अनियमितता की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है जिसे कौशल विकास मिशन सोसाईटी में 3-4 लाख रुपये प्रतिमाह के वेतन पर सीईओ नियुक्त किया है। क्योंकि उस व्यक्ति ने तो अपने आवेदन में अपनी योग्यता और अनुभव का सही विवरण दिया है। परंतु नियुक्ति के लिये प्रकाशित निविदा की शर्तों के आधार पर इन्हें नियुक्त करने वालों ने इसपर गौर क्यों नहीं किया कि यह विवरण सीईओ की नियुक्ति हेतु प्रकाशित निविदा में वर्णित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप नहीं है और उससे काफी कम है। इनकी योग्यता निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं होने के बाद भी कैसे और क्यों इन्हें नियुक्त कर लिया गया इसका कारण तो जांच के उपरांत ही पता चल सकेगा।

झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक ने आपको प्रेषित मेरी चर्चा टिप्पणी में उठाये गये बिन्दुओं का अनुपालन करते हुये मुझे जो दस्तावेज सौंपा हैं वे पूर्णतः अंग्रेजी में है। RFP और Contract Paper भी अंग्रेजी में है। इसलिये वस्तुस्थिति का बिन्दुवार विश्लेषण अंग्रेजी में भी संलग्न है, ताकि उर्पयुक्त वर्णित अनियमितताओं के बारे में अपना विचार सुनिश्चित करने में आपको सुविधा हो और अनियमितताओं पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्णय विवेचना के उपरांत आपके द्वारा लिया जा सके।

28/11/19  
सरयू राय

Analysis of Documents and Annexure submitted by JSDMS vide letter no. 30/2019-421 dated 15.02.2019 to Shri Saryu Roy, Minister, Govt. of Jharkhand.

Srl	RFP Reference	Point mentioned in the RFP	Non Compliance / Violation of RFP
1	RFP page no. 11 - General Provisions 2.1	Definitions: "Key Expert(s)" means an individual professional whose skills, sector experience, qualifications, knowledge and experience are critical to the performance of the Services under the Contract and whose CV is taken into account in the technical evaluation of the Technical Consultant's proposal & would be placed full-time at Jharkhand (SPMU) or New Delhi (CPMU), they need to be on the payroll of the Bidder.	<p>The definition of "Key Expert(s)" mentioned in the RFP is self explanatory and briefs the importance and criticality of the "Key Expert(s)" in technical evaluation of the proposals during selection process.</p> <p>While referring to Annexure-2 and Annexure-4 submitted by JSDMS on 15.02.19 It is evident that out of 15 key experts proposed by the Technical Consultant in the Proposal/Technical Bid only 7 key experts were deployed by the Technical Consultant. This is severe violation of RFP terms &amp; condition and Contract signed between the Govt. and Technical Consultant.</p> <p><b>Question:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deployment of "Key Expert(s)" is the most important factor in any Consultancy project. Kindly let us know under what circumstances was the Technical Consultant allowed to deviate majorly from the RFP clause and allowed to replace 8 Key Experts out of total 15 which is 50% of the total strength.</li> </ol> <p>Key experts are not on Payroll of the Bidder as mentioned in the RFP rather they are on Fixed Term Employment (contractual by nature) for 1 year. This is exploitation of Key Experts and also violation of RFP and Contract.</p> <p><b>Questions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. After deployment of Key Experts did JSDMS verify the employment status whether the resources are on Payroll of the Technical Consultant or Contractual?</li> <li>2. Is the employment of Key Experts on FTE (contractual basis for 1 year) by the Technical Consultant, the main reason for the 8 Key Experts not joining the Technical Consultant?</li> </ol>
2	RFP page no.15 - Proposal Validity 14.3	If it is established that any Key Expert nominated in the Technical Consultant's Proposal was not available at the time of Proposal submission or was included in the Proposal without his/her confirmation, such Proposal shall be disqualified and rejected for further evaluation.	Technical and Financial proposals were submitted on 27.10.2016. While referring to Annexure-4 submitted on 15.02.19 it is evident that the key experts were not associated with the Technical Consultant at the time of submission of proposal. All of them were working in different organizations. Nominated key experts for the PMU started joining from 5th June '17 onwards.

		<p>This is severe violation of RFP terms &amp; condition and Contract signed between the Govt. and Technical Consultant.</p> <p><b>Question:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Did JSDMS verify whether the nominated Key Experts were working with the Technical Consultant at the time of submission of proposal as mentioned in the RFP clause?</li> </ol>
<p>3 RFP page no.15 – Proposal Validity 14.4</p>	<p>Technical Consultant cannot change the Key Experts as submitted in response to the bid, except in case of resignation, medical incapacity or death, for the period of 2 years from the project start date unless there is written approval of the MISSION DIRECTOR of JSDMS, approval of which may be provided in very rare situation. The Key Experts have to be fulltime on this project and at the location mentioned as per the RFP. This clause is nonnegotiable and penalties to the extent of 50% of the fee for the Key Expert as mentioned in FIN 2 (per man month rate card) may be levied for the entire balance period of the contract for such change request, unless an acceptable replacement is provided within 60 days of such change request. After two years of the contract, Technical Consultant has to ensure that 60% of the proposed team of Experts remain unchanged. For any change request of Key Expert, the substitute has to be an individual with similar / better experience &amp; qualifications and accepted in writing by MISSION DIRECTOR of JSDMS.</p>	<p>As mentioned in Annexure-4 submitted on 15.02.19 it is evident that Technical Consultant has changed 50% key experts at the start of the project itself. 8 professionals out of 15 member SPMU team who were proposed in the technical proposal as experts did not join the project from the start because the Technical Consultant was offering FTE contractual positions instead of payroll jobs and the experts did not agree to join. One of the most important clause in the RFP is "After two years of the contract, Technical Consultant has to ensure that 60% of the proposed team of Experts remain unchanged". After 18 months itself only 4 key experts who were proposed in the response to the bid are working i.e.. only 25% team experts remain unchanged in place of 60% as required in the RFP.</p> <p>Technical consultant has violated this clause in two ways: First they have not deployed all the experts whom they had proposed in their Technical Bid and won the bid using their profile. Only 50% experts joined the organization. Secondly the technical consultant did not maintain the retention of 60% experts for two years. Only 25% proposed experts are working in the team after 18 months.</p> <p>This is severe violation of RFP terms &amp; condition and Contract signed between the Govt. and Technical Consultant.</p> <p><b>Questions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Why was the Technical Consultant allowed to deviate majorly from the RFP clause and replace 8 Key Experts out of total 15 which is 50% of the total strength of resources.</li> <li>2. Were the chairperson of the selection committee/Dept. Secretary informed about this major deviation and its consequences of RFP non-compliance?</li> <li>3. Who had given approval for replacement of 8 key experts out of total 15 key experts.</li> </ol>

			4. Why can this not be considered as – Just to win the bid the Technical Consultant proposed highly experienced & qualified Key Experts and later replaced them with lesser ones,
4	RFP page no.16 – Sub-Contracting 17.1	Sub-Contracting of Key Experts is not allowed and all the resources should be on the payroll of the Technical Consultant	<p>All the key experts are on Fixed Term Employment (Contractual) for 1 year only which is now being extended every 4-6 months only.</p> <p>8 Originally proposed resources did not join the Technical Consultant due to contractual position which led to replacement of key experts. As per RFP all the resources should be on the payroll.</p> <p>This is severe violation of RFP terms &amp; condition and Contract signed between the Govt. and Technical Consultant.</p> <p>Questions;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. After deployment of Key Experts did JSDMS verify the employment status whether the resources are on Payroll of the Technical Consultant or Contractual?</li> <li>2. Is the employment of Key Experts on FTE (contractual basis for 1 year) by the Technical Consultant, the main reason for the 8 Key Experts not joining the Technical Consultant?</li> </ol>
5	RFP page no.18 – Technical Proposal Format and Content 22.2	Technical Consultant shall not propose alternative Key Experts. Only one CV shall be submitted for each Key Expert position. Failure to comply with this requirement will make the Proposal non-responsive.	Technical Consultant has replaced 8 Key Experts in the beginning of the assignment which amounts to more than 50% of the total Key Experts deployed
6	RFP page no.18 – Technical Proposal Format and Content 22.3	Technical Consultant cannot change the Key Experts as submitted in response to the bid, except in case of resignation, medical incapacity or death, for the period of 2 years from the project start date unless there is written approval of the MISSION DIRECTOR of JSDMS, approval of which may be provided in very rare situation. The Key Experts have to be fulltime on this project and at the location mentioned as per the RFP. This clause is nonnegotiable and penalties to the extent of 50% of the fee for the Key Expert as mentioned in FIN 2 (per man month rate card) may be levied for the entire balance period of the contract for such change request, unless an acceptable replacement is provided within 60 days of such change request. After two years of the contract, Technical Consultant has to ensure that 60%	<p>As mentioned in Annexure-4 submitted on 15.02.19 it is evident that Technical Consultant has changed 50% key experts at the start of the project itself. 8 professionals out of 15 member SPMU team who were proposed in the technical proposal as experts did not join the project from the start because the Technical Consultant was offering FTE contractual positions instead of payroll jobs and the experts did not agree to join. One of the most important clause in the RFP is "After two years of the contract, Technical Consultant has to ensure that 60% of the proposed team of Experts remain unchanged". After 18 months itself only 4 key experts who were proposed in the response to the bid are working i.e. only 25% team experts remain unchanged in place of 60% as required in the RFP.</p> <p>This is severe violation of RFP terms &amp; condition</p>

		of the proposed team of Experts remain unchanged. For any change request of Key Expert, the substitute has to be an individual with similar / better experience & qualifications and accepted in writing by MISSION DIRECTOR of JSDMS.	and Contract signed between the Govt. and Technical Consultant.  Question: Same as point 3
7	RFP page no.18 – Financial Proposal 23.1	The Financial Proposal shall be prepared using the Standard Forms provided in Section 5 of the RFP. It shall include all costs associated with the assignment including all travel, lodging, boarding, communication (mobile and landline), IT infrastructure and consumables as required for the project, rentals etc. <b>State will not bear any cost other than the fee mentioned in the financial proposal.</b>	This clause in the RFP mentions that the <b>State will not bear any cost other than the fee mentioned in the financial proposal.</b>  Question: 1. Does JSDMS make any payments or reimbursements of expenses to Technical Consultants "Key Experts" for travel, lodging and boarding required for the project.
8	RFP page no.24 – Conduct of Technical Consultant Manpower 46.2 - 4	Technical Consultant cannot change the Key Experts as submitted in response to the bid, except in case of resignation, medical incapacity or death, for the period of 2 years from the project start date unless there is written approval of the MISSION DIRECTOR of JSDMS, approval of which may be provided in very rare situation. The Key Experts have to be fulltime on this project and at the location mentioned as per the RFP. This clause is nonnegotiable and penalties to the extent of 50% of the fee for the Key Expert as mentioned in FIN 2 (per man month rate card) may be levied for the entire balance period of the contract for such change request, unless an acceptable replacement is provided within 60 days of such change request. After two years of the contract, Technical Consultant has to ensure that 60% of the proposed team of Experts remain unchanged. For any change request of Key Expert, the substitute has to be an individual with similar / better experience & qualifications and accepted in writing by MISSION DIRECTOR of JSDMS.	As mentioned in Annexure-4 submitted on 15.02.19 it is evident that Technical Consultant has changed 50% key experts at the start of the project itself. 8 members out of 15 member SPMU team proposed by the Technical Consultant in the technical proposal as experts were not deployed.  One of the important clause in the RFP is "After two years of the contract, Technical Consultant has to ensure that 60% of the proposed team of Experts remain unchanged". The fact is after 18 months itself only 4 key experts who were proposed in the response to the bid are working i.e. only 25% team experts remain unchanged in place of 60% as required in the RFP.  This is severe violation of RFP terms & condition and Contract signed between the Govt. and Technical Consultant.  Question: 1. Let us know whether all the replaced Key Experts are individual with similar / better experience & qualification with whom they have been replaced. Please submit comparative details of each replaced key experts with their actual experience & qualification 2. Also let us know how many Key Experts are still working with JSDMS/PMU out of 15 initially proposed in the bid
9	RFP page no.38 – Technical Evaluation Criterion-Skill	Key Professionals: (Total = 45 Marks) 1. CPMU Manager (1) = 3 Marks 2. Project Director (1) = 8 Marks	The technical consultant secured marks on the basis of CVs of 15 key experts submitted along with the technical bid and easily qualified the bid but the fact is 8 out of 15 proposed Key Experts

<p>Sets of Key Professionals = 45 Marks</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Manager (Placement) (2) = 6 Marks</li> <li>4. Manager (Skill Gap and Training Needs Analysis) (2) = 4 Marks</li> <li>5. Social Mobilization – Media Manager (1) = 3 Marks</li> <li>6. Social Mobilization – Communication Manager (1) = 4 Marks</li> <li>7. Social Mobilization Expert (1) = 3 Marks</li> <li>8. Manager (IT/MIS/Web Management) (1) = 4 Marks</li> <li>9. Manager (Finance &amp; Administration) (1) = 4 Marks</li> <li>10. Manager – Sector Skill (4) = 4 Marks</li> <li>11. Call Centre Manager –Operations, Technology &amp; Content (1) = 2 Marks</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>Total Marks = 45</b></p>	<p>never joined the Technical Consultant whose marks made the Technical Consultant qualify the Bid.</p> <p>The following 8 proposed Key Experts did not join the Technical Consultant whose marks were added in the bid to Technically Qualify.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">2 Manager Placements Amit Sharma, Prashant Khare</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">= 6 marks</td> </tr> <tr> <td>2 Manager (Skill Gap and TNA) Vijay Subarna, Santa Prasad Roy</td> <td style="text-align: right;">= 4 marks</td> </tr> <tr> <td>1 Manager (IT/MIS/Web Management) Tanul Rustagi</td> <td style="text-align: right;">= 4 marks</td> </tr> <tr> <td>2 Manager – Sector Skill Sakesh Kumar, Bhushan Ranjan</td> <td style="text-align: right;">= 2 marks</td> </tr> <tr> <td>1 Call Centre Manager-Operations</td> <td style="text-align: right;">= 2 marks</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><b>Total Marks Short = 18</b></p> <p><b>Questions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If the Technical Consultant could not deploy the 8 Key Experts as proposed in their Technical Bid which formed the basis for their technically qualifying the bid then how come they were awarded the Contract? The Technical Consultant is short by 18 marks in the technical qualification.</li> <li>2. The LOI was issued on 28<sup>th</sup> May 17 with team deployment time given to Technical Consultant of 30 days. The contract was signed on 29<sup>th</sup> June 17. If the Technical Consultant could not deploy the complete team within 30 days then why was the Contract hurriedly signed? It could have been deferred till full deployment of team and compliance of RFP.</li> </ol>	2 Manager Placements Amit Sharma, Prashant Khare	= 6 marks	2 Manager (Skill Gap and TNA) Vijay Subarna, Santa Prasad Roy	= 4 marks	1 Manager (IT/MIS/Web Management) Tanul Rustagi	= 4 marks	2 Manager – Sector Skill Sakesh Kumar, Bhushan Ranjan	= 2 marks	1 Call Centre Manager-Operations	= 2 marks
2 Manager Placements Amit Sharma, Prashant Khare	= 6 marks											
2 Manager (Skill Gap and TNA) Vijay Subarna, Santa Prasad Roy	= 4 marks											
1 Manager (IT/MIS/Web Management) Tanul Rustagi	= 4 marks											
2 Manager – Sector Skill Sakesh Kumar, Bhushan Ranjan	= 2 marks											
1 Call Centre Manager-Operations	= 2 marks											
<p>10 RFP page no.24 – Conduct of Technical Consultant Manpower 46.2 - 4</p>	<p>For any change request of Key Expert, the substitute has to be an individual with similar / better experience &amp; qualifications</p>	<p>As mentioned in Annexure-4 submitted by JSDMS on 15.02.19 it is evident that the Technical Consultant has replaced the following two key experts:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Earlier working Project Director was having over 24 years of work experience who has been replaced with new Project Director who has less than 10 years of work experience</li> <li>2. Earlier working Manager Social Mobilization-Communication was having over 14 years of</li> </ol>										

work experience who has been replaced with new Expert who has about 4 years of work experience

3. In both the case this is violation of RFP terms & condition and in one way it also shows JSDMS being liberal with the Technical Consultant

**Questions:**

1. Under what circumstances did JSDMS approve deployment of both the Key Experts? Project Director being the most important team member and leader of the team has been replaced with lesser work experience than earlier Key Expert and Manager Social Mobilization-Communication has also been replaced with lesser work experience than earlier Key Expert and also as asked in the RFP (7 years). Shall this not be considered as - The Technical Consultant is not capable of providing higher experienced Key Experts for the project as they had deployed earlier and also as mentioned in the RFP.
2. Why can this not be considered as - Just to win the bid the Technical Consultant initially deployed highly experienced & qualified Key Experts and later replaced them with lesser ones?

**Summarized Important Questions:**

1. Why was the Technical Consultant allowed to deviate majorly from the RFP clause and replace 8 Key Experts out of total 15 which is 50% of the total strength of resources? Were the chairperson of the selection committee/Dept. secretary informed about this major deviation and its consequences of RFP non-compliance? Who has given approval for replacement of 8 key experts out of total 15 key experts? Why can this not be considered as - Just to win the bid the Technical Consultant proposed highly experienced & qualified Key Experts and later replaced them?
2. If the Technical Consultant could not deploy the 8 Key Experts as proposed in their Technical Bid which formed the basis for their technically qualifying for the bid then how come they were awarded the Work Order? Who approved the signing of contract and release of Work Order? The LOI was issued on 28<sup>th</sup> May'17 with team deployment time given to Technical Consultant of 30 days. The contract was signed on 29<sup>th</sup> June'17. If the Technical Consultant could not deploy the complete team within 30 days from issuance of LOI then why was the Contract hurriedly signed?
3. Did JSDMS verify whether the nominated Key Experts were working with the Technical Consultant at the time of submission of proposal as mentioned in the RFP clause 14.3? After deployment of Key Experts did JSDMS verify the employment status whether the resources have been hired by the Technical Consultant on Payroll or Contractual Basis for 1 year only as required by RFP clause 17.1? Is the employment condition of Key Experts on Contractual basis for 1 year the reason for 8 Key Experts not joining the Technical Consultant?

## Other Questions

4. In addition to the Consultancy Fee, Does JSDMS make any other payments or reimbursements of expenses to Technical Consultant's "Key Experts" for travel, lodging and boarding required for the project.
5. Let us know whether all the replaced Key Experts are individual with similar or better experience & qualification with whom they have been replaced with. Please submit comparative details of each replaced key experts with their actual experience & qualification
6. Also inform how many Key Experts are still working with JSDMS State PMU out of 15 initially proposed in the bid
7. Two Key Experts - Project Director and Manager Social Mobilization-Communication has been recently replaced. Project Director being the most important team member and leader of the team, has been replaced with much less work experience than earlier deployed. Manager Social Mobilization-Communication has also been replaced with lesser work experience than earlier Key Expert and also not as per RFP clause (7 years). Why shall this not be considered as - The Technical Consultant is not capable of providing higher experienced Key Experts for the project as they had deployed earlier and also as mentioned in the RFP. This is violation of RFP clause.

Saryu Roy  
29.07.19

Saryu Roy